12 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता के

अब 13 वें वर्ष की ओर

पाठकों/दर्शकों का असीम स्नेह

Bharatsamman.com | Bharat samman | Bharat Samman

RNI No. CHHHIN/2011/38292

भारत सम्मान NEWS

हो जाओ सावधान...

वर्ष-13 अंक-149 | अम्बिकापुर, बुधवार, 22 नवम्बर 2023 | कुल पृष्ठ-4 मूल्य-1.00 रू.

पराली जलाने वालों को एमएसपी नहीं दिया जाना चाहिए, वायु प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को दी सलाह

नई दिल्ली। कोर्ट के आदेश के बावजूद पंजाब में पराली जलना बंद न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें कोई आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। जिन्होंने पराली जलाई है और रेड फ्लैग हैं, उन पर एफआइआर दर्ज होने और जुर्माना लगाने के अलावा ऐसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, जिससे उनकी जेब पर चोट हो।

जब हरियाणा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं

कोर्ट ने पराली जलने से रोकने में पंजाब सरकार के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब हरियाणा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह अगली तारीख पर बताएगी कि उसने पराली जलाने पर कितने किसानों पर जुर्माना लगाया और उसमें से कितना वसूला गया।

इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए

कोर्ट ने आज फिर कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक-दूसरे पर आरोप मढ़ने या एक को दूसरे से तुलना नहीं की जानी चाहिए। केंद्र और राज्य को राजनीति भूल कर दीर्घकालिक हल ढूंढना चाहिए। ये टिप्पणियां, सुझाव और आदेश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान दिये। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई कोर्ट ने पंजाब के एडवोकेट जनरल से पूछा कि आपके यहां पराली जलने का क्या हाल है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट सचिव के साथ संबंधित राज्यों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो तय हुआ है, उसे लागू करने का शिड्यूल होना चाहिए। पीठ ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए पूछा कि पराली जलने से रोकने पर क्या हुआ। कोर्ट ने आदेश में थानाध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया था।

हरियाणा-यूपी कर सकते हैं तो पंजाब क्यों नहीं

कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर छोटे किसान मशीन किराए पर लेने और उसमें ईंधन व श्रमिक का खर्च नहीं उठा पा रहे तो सरकार 100 फीसद आर्थिक मदद दे और पराली खुद ले ले, जिसे बाद में वह उससे लाभ कमा ले। कोर्ट ने कहा कि अगर हरियाणा और यूपी ऐसा कर सकता है तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। वास्तविकता यह है कि पंजाब में पराली अभी भी जल रही है।

फारमर इज विलेन, बट विलेन इज नाट हियर

सुनवाई के दौरान पीठ के दूसरे न्यायाधीश सुधांशु धूलिया ने कहा कि जिन किसानों के बारे में आदेश दिया जा रहा है, वे कहां हैं। किसानों की ओर से कौन पेश हो रहा है। किसान विलेन हैं, लेकिन यहां विलेन मौजूद नहीं है। जस्टिस धूलिया ने कहा कि जरूर कुछ कारण होंगे, जिसकी वजह से वे ऐसा कर रहे हैं। अटार्नी जनरल ने कहा कि किसान यहां जानबूझकर नहीं आ रहे हैं। राज्य सरकार इस पर जवाब देगी कि क्यों कर रहे हैं। जस्टिस धूलिया ने कहा कि राज्य इसका जवाब नहीं दे रहा। जस्टिस कौल ने कहा कि उनका मानना है कि इस सबका निष्कर्ष पैसा है। किसान चाहते हैं कि या तो उन्हें पराली से निबटने के लिए पूरा पैसा दिया जाए या फिर वे किसी की सुनेंगे ही नहीं। एक वकील ने कहा कि किसान बात को समझते ही नहीं हैं। यह भी कहा गया कि एमएसपी संवेदनशील मुद्दा है।

पंजाब में जमीन सूख रही है

जस्टिस कौल ने पंजाब की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि पंजाब में जमीन सूखती जा रही है। जमीन के नीचे का पानी सूखता जा रहा है। किसानों को यह बात समझनी होगी। जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि आप व्यापक पहलू पर विचार करें। धान के बजाए किसी वैकल्पिक फसल पर विचार होना चाहिए।

दिल्ली-यूपी से मांगी रिपोर्ट

खुले में कचरा जलाने के मामले में कोर्ट ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश कोर्ट ने लोनी और गाजियाबाद में कचरा जलने की घटनाओं का जिक्र होने पर दिये। कोर्ट ने पुराने वाहनों में रंगीन स्टीकर लगाने के बारे में भी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को विचार करने को कहा है। साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी विचार करने को कमेटी से कहा है।

पंजाब ने क्या कहा?

पंजाब ने कहा कि पहले की तुलना में पराली जलना कम हुआ है। 984 एफआइआर दर्ज की गई हैं। दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। खेत में पराली जलना रोकने के लिए उड़न दस्ते बनाए गए हैं, लेकिन लोग उन्हें पहुंचने नहीं देते, रास्ता बाधित किया जाता है। कानून व्यवस्था की भी दिक्कत हो रही है। इस पर पीठ ने कहा कि आदेश में एसएचओ को जिम्मेदार बनाया गया है। आप कानून व्यवस्था की बात नहीं कह सकते। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब ने सिर्फ 6621 पर्यावरण क्षति पूर्ति लगाई है। पंजाब ने 3415 चालान हुए और 86.8 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया और 473 एफआइआर दर्ज हुई हैं।

कोर्ट ने पंजाब से किया सवाल

कोर्ट ने पंजाब से सवाल किया कि जुर्माना सिर्फ लगाया गया है कि वसूला भी गया है। अगली तारीख पर बताना होगा कि कितना जुर्माना वसूला गया। पंजाब ने कहा कि छह जिलों में पूरी तरह से पराली जलना बंद हो चुकी है। कोर्ट ने पंजाब को समस्या का हल बताते हुए कहा कि जो लोग पराली जला रहे हैं, उन्हें आर्थिक लाभ क्यों मिलना चाहिए। पराली जलाने वाले किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि धान की जगह वैकल्पिक फसल का सुझाव दीर्घकालिक योजना है, लेकिन अभी उनका लाभ रोका जाना चाहिए। जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी जेब पर चोट पड़नी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने पराली का पूरा काम मैकनाइज करने का भी सुझाव दिया और कहा कि इसमें फायदा है। बड़े किसान इससे भी लाभ कमा रहे हैं।

22 जनवरी को अयोध्या में मनेगी दूसरी दिवाली

एमपी के 25 लाख से अधिक परिवारों को पीले चावल से मिलेगा निमंत्रण

भोपाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर अयोध्या में आगामी जनवरी में होने वाले राम लला के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमित्त मध्यभारत प्रांत के 25 लाख से अधिक परिवारों को निमंत्रण देंगे। इसके लिए श्री राम मंदिर में पूजित अक्षत (पीले चावल) कलश संगठन की दृष्टि से बने हमारे मध्यभारत प्रांत आ चुके हैं।

इन पूजित अक्षत कलश का जिला सह वितरण मंगलवार को गुफा मंदिर लालघाटी से किया गया। इस मौके पर संगठन के 32 जिलों के प्रतिनिधि पूजित अक्षत कलश अपने जिलों में ले जाने के लिए उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख जितेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक तीर्थ क्षेत्र न्यास के आह्वान पर इस अक्षत निमंत्रण को लेकर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता अन्य हिंदू संगठनों के साथ मिलकर एक जनवरी से 15 जनवरी के बीच प्रांत के नगर ग्रामों में हिंदू परिवारों तक जाएंगे।

हम भगवान श्रीराम के 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटने की खुशी में प्रति वर्ष दिवाली मनाते हैं। इस बार आगामी 22 जनवरी को तो वह दूसरी दीपावली होगी, जब रामजी 500 वर्षों के बाद, भारत की स्वतंत्रता की अमृत बेला में अपने जन्म-स्थान पर लौटेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि विश्व का समस्त हिंदू समाज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रत्यक्ष शामिल हो। सब रामभक्तों को तो उस दिन अयोध्या नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए विहिप का आह्वान है कि प्रांतभर के हिंदू अपने मुहल्ले या गांव के मंदिर को ही अयोध्या मानकर वहां एकत्र हों। वहां की परंपरानुसार पूजा-पाठ, आराधना व अनुष्ठान करें। पूज्य संतों द्वारा दिए गए विजय महामंत्र श्रीराम-जय राम-जय जय राम का जाप करें। साथ ही अयोध्या के भव्य-दिव्य कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को साक्षात देखें।

आरती में अपना स्वर मिलाए। प्रसाद बांटें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनकर आनंद मनाएं। विहिप ने देश को 45 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में उस भाग के लिए निश्चित दिन अयोध्या पधारने का निवेदन किया है। इसी क्रम मे मध्यभारत प्रांत से दिनांक 17 फरवरी को लगभग 2500 लोगों के दर्शनों की व्यवस्था की गई है।

गणमान्य नागरिक मौजूद थे

गुफा मंदिर में हुए कार्यक्रम में पूज्य साध्वी महामंडलेश्वर प्रज्ञा भारती, महंत रामदास त्यागी महाराज, महंत अनिलानंद महाराज, महामंडलेश्वर राम भूषण दास महाराज, महंत राधा मोहन दास महाराज, महंत रविन्द्र दास महाराज, सुदेश शांडिल्य महाराज, विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष हुकुमचंद सावला, संघ के प्रांत संघचालक अशोक पांडे, विहिप प्रांत अध्यक्ष पीतांबर राजदेव एवं संघ परिवार के अन्य संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी, समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद थे।

12 वर्ष निर्भीक पत्रकारिता के

'सत्ता की चाटुकारिता नहीं जनपक्षीय पत्रकारिता'

आमजन, गरीब-मज़लूमों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता का नाम है भारत सम्मान, जब शासन-सत्ता में बैठे ऐसे लोग जो पद-पावर के नशे में चूर होकर करते हैं अपने कर्तव्यपालन में चूक तो भारत सम्मान करता है उन्हें दुरुस्त...

2011 से भारत सम्मान आगे बढ़ रहा है और मिसाल क़ायम कर रहा है ईमानदार पत्रकारिता की..

भारत सम्मान दैनिक समाचार पत्र के साथ-साथ वेबसाईट - www.bharatsamman.com, फेसबुक पेज - Bharat Samman व यू-ट्यूब - Bharat Samman News के माध्यम से जनहित के खबरों को प्राथमिकता देते हैं। हमारा दावा है यदि आप पर जुल्म हुआ है, आप न्याय के लिए कर रहे हैं संघर्ष तो केवल एक ही नाम आपको याद होना चाहिए...

भारत सम्मान

इसी क्रांतिकारी मुहिम से निम्न जगहों पर जुड़ने के लिए सम्पर्क करें

छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, उतराखण्ड, बिहार, बंगाल व देश के सभी राज्यों में ब्यूरो व संवाददाता बनने संपर्क कर सकते हैं।

इन पदों में होंगे नियुक्त...

1 - राज्य ब्यूरो प्रमुख
2 - राज्य अपराध ब्यूरो प्रमुख
3 - जिला ब्यूरो प्रमुख
4 - जिला अपराध ब्यूरो प्रमुख
5 - तहसील संवाददाता
6 - तहसील अपराध संवाददाता

अपना फोटो लगा बायोडाटा हमारी ई-मेल आईडी bharatsammannews@gmail.com या व्हाट्सएप No. 07828866957 पर भेजे।

नोट

1. केवल ईमानदार लोग ही संपर्क करें, पत्रकारिता के नाम पर वसूली करने अथवा ब्लैकमेल करने वालों से हमारा कोई वास्ता नहीं
2. यहां नौकरी नहीं दी जाती है, यदि हमारे संस्था के नाम का गलत इस्तेमाल करता है, तो हमारे द्वारा जारी नंबर पर शिकायत जरूर करें।

प्रसार/प्रबंध सम्पादक
भारत सम्मान न्यूज नेटवर्क
07828866957
09303890212

संपादकीय

चिराग पासवान का इंतजार लंबा हो रहा है

अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान का इंतजार लंबा होता जा रहा है। उनको 12, जनपथ का बंगला खाली करके नॉर्थ एवेन्यू में रहना पड़ रहा है और नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के 15 महीने बाद भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली है। अब भी उनके पिता की बनाई पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके चाचा पशुपति पारस केंद्र सरकार में मंत्री हैं। जुलाई में एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में उनको गले लगाया था और उससे पहले जेपी नड्डा ने उनको लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य धड़े का नेता बताया था उससे लग रहा था कि उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन इनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब एक बार फिर इस बात की चर्चा हो रही है कि उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। उनके समर्थक कह रहे हैं कि किसी भी समय प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें चिराग पासवान को मंत्री बनाया जाएगा। पिछले कुछ समय उनको राज्यमंत्री बनाए जाने की बात बिहार भाजपा के नेता भी कह रहे हैं। नीतीश की काट में भाजपा को दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता को आगे करना है। तभी यह भी चर्चा है कि किसी अति पिछड़ी जाति के नेता को भी केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि बिहार में जाति गणना के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 36 फीसदी आबादी अत्यंत पिछड़ी जाति की है। यहां तक कहा जा सकता है कि भाजपा अति पिछड़ी जाति के ऐसे नेता को भी केंद्र में मंत्री बना सकती है, जो सांसद न हो। बिहार की जातीय राजनीति को देखते हुए मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल का मामला दिलचस्प हो रहा है।

इंटरनेट मीडिया से सरकार बनाने का दावा, सकारात्मक टिप्पणियों को पार्टियां बता रहीं जीत का आधार

रायपुर। प्रदेश में कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य राजनीतिक दल अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मतदाताओं के फीडबैक ले रहे हैं। फेसबुक, वाट्सएप, इंटरनेट मीडिया एक्स और इंस्ट्राग्राम जैसे प्लेटफार्म में लोगों की टिप्पणियों को भी पढ़ा जा रहा है। इसी के साथ टेलीफोन करके भी कुछ एजेंसियां पार्टियों के लिए फीडबैक ले रही हैं कि उन्होंने किस दल को वोट दिया है। कांग्रेस-भाजपा दोनों ही दलों ने अपने-अपने आंतरिक सर्वे के आधार पर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है।कांग्रेस का दावा है कि वह प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से 75 पार का आंकड़ा पार करेगी, जबकि भाजपा का दावा है कि वह 52 से 54 सीटें हासिल करेगी।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी पार्टी के पक्ष में लहर जैसी कोई बात नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जिसकी सरकार बनेगी, वह पार्टी बमुश्किल 47 से 48 विधायकों के आंकड़े के आसपास पहुंच पाएगी। मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों और विभिन्न स्रोतों से मिल रही जानकारी के आधार पर देखा जाए तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक-एक सीट पर कड़ा मुकाबला है। कहा जा रहा है कि यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो सरकार बनाने वाली पार्टी बहुमत के आसपास ही विधायक पाएगी। निर्दलीय व अन्य पार्टियों के विजयी उम्मीदवारों का महत्व बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

कांग्रेस के लिए इंटरनेट मीडिया पर सकारात्मक विचार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी आइटी एवं इंटरनेट मीडिया के प्रदेशाध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा ने कहा कि जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तभी से हम इंटरनेट मीडिया पर लगातार सक्रिय रहे। हमने वाररूम बनाया। हम लगातार लोगों के विचारों पर निगरानी करते रहे। इसका प्रभाव हमने देखा कि लाखों सकारात्मक टिप्पणी कांग्रेस के लिए हुई है। सबसे अधिक छत्तीसगढ़िया छवि और राज्य सरकार की गोबर-गोठान समेत अन्य योजनाओं को लोगों ने सराहा। किसानों के लिए कर्ज माफी बड़ी घोषणा थी। इसके बारे में लोगों ने अच्छे विचार प्रकट किए। इंटरनेट मीडिया पर जो प्रतिक्रिया दिख रही है, उससे कांग्रेस की सरकार के पुन- आने का संकेत मिल रहा है। जब हम 10 हजार टिप्पणी को ट्रेस करते हैं तो उनमें नौ हजार कमेंट कांग्रेस सरकार के पक्ष में मिले। हम इंटरनेट मीडिया के माध्यम से 90 लाख लोगों के साथ लगातार संपर्क में रहे।

मतदान के दिन ही इंटरनेट पर मिले रुझान

छत्तीसगढ़ भाजपा इंटरनेट मीडिया के प्रदेश सह संयोजक मितुल कोठारी ने बताया कि चुनाव के दिन ही पार्टी ने इंटरनेट मीडिया में आई टिप्पणियों की लगातार निगरानी की। इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म की निगरानी में हम काफी आगे रहे। सुबह से ही इंटरनेट मीडिया में पोस्ट शुरू हो गई थी और इसी के साथ जो बढ़त बनी, वह देर रात तक बनी रही। इस मामले में कांग्रेस की इंटरनेट मीडिया शुरूआत से ही पीछे रही और लगातार पीछे होती चली गई। भाजपा ने दावा किया कि भाजपा के फेसबुक, इंटरनेट मीडिया एक्स पर सुबह छह बजे से ही पोस्ट आनी शुरू हो गई थी। इस पर प्रतिक्रियाओं का भी दौर बड़ी तेजी से शुरू हुआ और लोगों मे भाजपा के इंटरनेट मीडिया के पोस्ट का लगातार इंतजार होता रहा। कांग्रेस की पहली पोस्ट सुबह 7-30 बजे के बाद शुरू हो पाई। भाजपा की इंटरनेट मीडिया टीम ने फेसबुक पर 32 वीडियो और 15 ग्राफिक्स पोस्ट किया। जिस पर 32,185 लाइक्स मिले और 2,079 ने शेयर किया। वहीं, इस दौरान कांग्रेस केवल दो वीडियो और 19 ग्राफिक्स ही पोस्ट कर पाई। जिसे केवल 2,782 लाइक्स मिले और 114 शेयर हो सके। इसी तरह हर प्लेटफार्म पर कांग्रेस पीछे रही।

आंवला पेड़ की पूजा-अर्चना कर मांगी गई मनोकामनाएं

आंवला नवमी पर कई जगह वनभोज का उठाया गया आनंद

रायगढ़। आवंला नवमी का विशेष महत्व है और इस दिन लोग आवंला पेड़ की पूजा कर मनोकामनाएं मांगते हैं। मंगलवार को आवंला नवमी को लेकर श्रद्धालुओं ने आवंला पेड़ की विधि विधान से पूजा अर्चना की, तो साथ ही पिकनिक स्थलों पर वनभोज का भी जमकर आनंद उठाया।

आंवला नवमी पर हर साल पिकनिक स्थलों में पर्यटकों की भीड़ होती है। मंगलवार को आवंला नवमी के दिन लोग आवंला पेड़ के नीचे पहुंचे और यहां पूजा अर्चना करने के साथ ही हाथ जोड़कर मनोकामनाएं भी मांगी। इसके अलावा इस दिन वनभोज करने की भी परंपरा चली आ रही है। ऐसे में पर्यटक पिकनिक स्थलों पर पहुंचते हैं। मंगलवार को शहर के सबसे करीब के पिकनिक स्थल पर पर्यटक पहुंचे और यहां वनभोज का भी जमकर आनंद उठाए, लेकिन इस बार पिछले साल की तुलना में भीड़ काफी कम था। क्योंकि पूर्व में इंद्रा विहार में खाना बनाने में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में इसका असर आंवला नवमी पर भी देखा गया।

हो जाती थी सुबह से भीड़

आंवला नवमी के दिन इंदिरा विहार में सुबह से ही पर्यटकों की भीड़ आनी शुरू हो जाती थी। लोग अलग अलग जगहों पर चुल्हा में अपना खाना बनाते थे और वनभोज का भरपूर लुत्फ उठाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नही था। काफी कम संख्या में पर्यटक यहां पहुंचे थे। हां यह बात जरूर है कि आंवला पेड़ का पूजा करने जरूर शहरवासी यहां आ रहे थे।

प्रतिदिन विलंब से पहुंच रहा ट्रेन, यात्रियों को उठानी पड़ रही परेशानी

कोरबा। ट्रेनों की लेटलतीफी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरबा आने वाली सभी ट्रेन अपने निर्धारित समय से कम से कम एक घंटा विलंब से पहुंच रही है। ऐसे में स्टेशन से घर जाने पर यात्रियों को अन्य परेशानियों से जूझना पड़ता है। विशाखापट्टनम-कोरबा लिंक एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा शिवनाथ, हसदेव एक्सप्रेस भी विलंब से पहुंची। इससे सफर करने वाले यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। लिंक व शिवनाथ एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से यानी दोपहर सवा एक बजे के बाद कोरबा पहुंच रही हैं। जबकि इसका कोरबा आने का समय सुबह 11.15 बजे निर्धारित है। वहीं शिवनाथ एक्सप्रेस का कोरबा पहुंचने का समय सुबह लगभग नौ बजे है। लेकिन ट्रेन रोजाना विलंब से पहुंच रही है। इससे यात्री समय पर गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी शासकीय व निजी संस्थानों के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों को हो रही है। उन्हें कार्यालय पहुंचने में विलंब हो रही है। बावजूद इसके ट्रेन को समय पर चलाने को लेकर रेल प्रबंधन गंभीर नहीं है। प्रबंधन की ओर से उरगा तक आटो सिग्नलिंग का लगभग कार्य पूरा होने की बात कही जा रही है, पर इससे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है।

शार्ट सर्किट से लगी आग से सिलेंडर ब्लास्ट, पूरा घर जल कर खाक

कोरबा। पंप हाउस कालोनी के एक आवास में शार्ट सर्किट की वजह से लगी आग गैस सिलेंडर, बाइक तक पहुंच गई और ब्लास्ट हो गया। इससे घर में रखा पूरा सामान जल कर खाक हो गया। घटना के वक्त आवास में निवासरत एसईसीएल कर्मी सपरिवार बिलासपुर गया था। घटना में सुखद यह रहा कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, पर कर्मी को लाखों रूपये की आर्थिक क्षति पहुंची है। साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्डिस लिमिटेड (एसईसीएल) की विभागीय कालोनी पंप हाउस में माइनस टाइप आवास क्रमांक एम-187 में बालेश्वर सिंह अपनी पत्नी व दो पुत्र के साथ निवासरत हैं। कुसमुंडा में ड्यूटी करने वाले बालेश्वर सिंह मंगलवार की सुबह ही किसी कार्य से सपरिवार बिलासपुर गए थे। बताया जा रहा है कि घर में उन्होंने स्टेब्लाइजर को बंद नहीं किया था। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि वोल्टेज अधिक होने की वजह से स्टेब्लाइजर गर्म हो गया और शार्ट सर्किट हो गया। इसे आग लग गई, जो पहले इनवर्टर में पहुंची और भड़क गई। इस बीच घर से धुआं निकलता देख लोगों को पहले

कुछ समझ नहीं आया। तब तक एसी को अपनी चपेट में लेने के बाद आग रसोई तक पहुंची जहां रखा गैस सिलेंडर व फ्रीज में भी आग लग गई। इसके साथ ही जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर फटने से घर में रखे सभी सामान में आग लग गई। तह आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली और आनन फानन में पानी डाल कर आग बुझाने का प्रयास किया, पर आग की भयानकता को देख कर कोई भी अंदर जाने से डर रहा है, क्योंकि घर के अंदर रखी बाइक भी जल रही थी, इसलिए पेट्रोल टंकी फूटने का भय था। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर पानी डाल कर आग को बुझाने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिल सकी। लगातार आग बढ़ने से लोगों में भय होने लगा कि कहीं आग आसपास के घरों को अपनी चपेट में न ले लें। स्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। इस बीच किसी ने घटना की जानकारी सीएसईबी पुलिस व दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस व दो दमकल स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लगभग दो घंटे की अथक मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। इसके बाद पुलिस व दमकल कर्मी घर के अंदर घुसे, तो पूरा सामान जला हुआ मिला। केवल एक तिजोरी ही बची हुई मिली। मामले में सीएसईबी पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया शार्टसर्किट की वजह से लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मकान मालिक के वापस आने पर आगजनी की क्षति का आंकलन किया जा सकता है।

सूचना मिलने पर वापस लौटा परिवार

मकान से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों को थोड़ा संदेह हुआ और उन्होंने पानी का डालने का प्रयास करने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, पर सफल नहीं हो सके। तब छत पर जाकर पानी डालने का प्रयास किए, इससे भी कोई राहत नहीं मिल सकी। इस बीच आग लगने की जानकारी होते ही आसपास के लोगों ने बालेश्वर सिंह व उसके परिवार को दिया। दोपहर बाद परिवार के सदस्य वापस घर लौटे और नुकसान का आंकलन कर रहे हैं।

मकान की दीवार में कहीं दरार तो कहीं टूटी

फ्रिज व गैस सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए ब्लास्ट से मकान भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। 50 साल से भी ज्यादा पुराना मकान है। चूंकि पहले की ईंट की चौड़ाई व जोड़ाई काफी मजबूत थी, इसलिए कई मकान की दीवार में कई स्थान पर दरार आ गया है। वहीं कुछ स्थान पर दीवार टूट गई है। वहीं मकान के पिछले हिस्से की छत में भी दरार आ गया है। इससे मकान भी अब रहने के लायक नहीं रह गया है। मकान का सामान भी कबाड़ में बेचने के लायक की स्थिति में है।

RNI No. CHHHIN/2011/38292
भारत सम्मान NEWS
अम्बिकापुर, बुधवार, 22 नवम्बर 2023

बधियाकरण करने एक करोड़ से ज्यादा का बजट, खर्च ही नहीं कर पा रहे जिम्मेदार

दो वर्ष से बढ़ा बजट

नगर निगम के आंकड़े बताते हैं कि दो वर्ष पहले तक यानी कि 2021-22 में बधियाकरण के लिए सिर्फ 15-16 लाख रुपये का ही बजट रखा गया था, लेकिन इसके बाद पिछले दो वर्षों से इसका बजट बढ़ाकर एक करोड़ रुपये से भी अधिक कर दिया गया है। लेकिन न तो पिछले वर्ष इसके बजट का कोई विशेष उपयोग किया गया और न ही इस बार कोई उपयोग होता दिखाई दे रहा है।

बजट बढ़ाने का भी प्रविधान

निगम को मामले की गंभीरता की स्थिति में बजट बढ़ाए जाने का भी प्रविधान है। इसके लिए जो भी बजट स्वीकृत किया जाता है, इसके अलावा अन्य मदों में भी इसकी व्यवस्था करते हुए बधियाकरण में तेजी लाई जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद निगम का उदासीन रवैया बना ही रहता है।

कुत्तों समस्या के लिए मेनका गांधी जिम्मेदार

हाईकोर्ट अधिवक्ता दुर्गा शंकर सिंह ने कहा कि कुछ वर्षों पहले तक निगम हर छह महीने में कुत्तों को जहर देकर मारती थी। इस पर पशु अतिचार अधिनियम मेनका गांधी की पहल पर इस पर रोक लगाई गई। जिससे कुत्तों की आबादी बढ़ी और लगाता बढ़ती जा रही है। इसी की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जिसमें लोग दुर्घटना का शिकार होने के साथ ही डाग बाइट के शिकार भी हो रहे हैं।

रायपुर। शहर में श्वानों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, नगर निगम का अमला भी इसे लेकर प्रापर व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि पिछले दो वर्षों से श्वानों के बधियाकरण के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक का बजट रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद शहर में श्वानों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनका आतंक भी बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष यानी कि 2022-23 में बधियाकरण के लिए 1.21 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था, लेकिन श्वानों का बधियाकरण सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। वहीं, इस वित्तीय वर्ष के लिए फिर से 1.30 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, इसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार खुद इसे स्वीकार रहे हैं, कि कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है, कि निगम की कार्यशैली किस प्रकार की है।

फैक्ट फाइल

10 हजार से ज्यादा शहर में आवारा कुत्ते।

1.31 करोड़ रुपये का इस वित्तीय वर्ष में बजट।

1.21 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष का बजट।

16-17 श्वानों के रोज बधियाकरण का दावा।

425 श्वानों के बधियाकरण महीने में करने का दावा।

करोड़ों का बजट फिर भी नहीं हो रहा उपयोग

हर वर्ष करोड़ों रुपये का बजट रहता है। जरूरत पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इसका कोई खास उपयोग होता नहीं दिखाई देता है। इसी असंवेदनशीलता की वजह से लोगों को डाग बाइट का शिकार होना पड़ता है।

मीनल चौबे, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम, रायपुर

बधियाकरण में तेजी लाने के दिए निर्देश

हमारी डाग कैचर टीम लगातार क्षेत्रों का निरीक्षण करती है और बधियाकरण भी करती है। जहां इसकी शिकायतें आती हैं, उनके अलावा जहां इस तरह की जरूरत महसूस होती है। वहां कार्रवाई की जाती है। इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

नागभूषण राव, अध्यक्ष, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, रायपुर

हर माह आते हैं दर्जनों मामले

मातृ स्मृति अस्पताल मेडिकल स्टोर की संचालक किशोर सहारिया ने कहा कि गुढ़ियारी क्षेत्र के शुक्रवारी बाजार में कुत्तों का झुंड सड़क पर अकसर बैठा रहता है, जो कि आने जाने वाले दोपहिया वाहन चालकों को दौड़ाते हैं। साथ ही उन्हें काटते भी हैं। इसकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं। अस्पताल नजदीक होने के कारण हर महीने दर्जनों डाग बाइट के मामले आते हैं।

आरडीए की दुकानें फ्री होल्ड पर उपलब्ध, 30 नवंबर तक चुकाना है कर्ज

रायपुर। आरडीए (रायपुर विकास प्राधिकरण) इस महीने के आखिर यानी 30 नवंबर तक पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहता है। इसके तहत पिछले दिनों प्लाट बिक्री के बाद आरडीए द्वारा शहर की व्यस्ततम मार्ग की दुकानें और हाल फ्री होल्ड पर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए निविदा भी निकाली गई है। मालूम हो कि आरडीए पर लगभग 19 करोड़ का कर्जा और बाकी है। 25 अक्टूबर और आठ नवंबर को प्लाटों की हुई बिक्री में आरडीए को लगभग 62 करोड़ से ज्यादा की राशि मिल चुकी है। आरडीए से मिली जानकारी के अनुसार भक्त माताकर्मा परिसर न्यू राजेन्द्र नगर में 478 से 494 वर्गफुट के 11 नग दुकानें फ्री होल्ड पर आफसेट दर 5,500 रुपये प्रति वर्गफुट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही डा. खूबचंद बघेल (रावांभाठा) ट्रांसपोर्ट नगर योजनांतर्गत 92 से 552 वर्गफुट की 25 नग दुकानें लीज होल्ड पर आफसेट दर 1,550 रुपये प्रति वर्गफुट पर उपलब्ध है। शैलेंद्र नगर योजना में आफसेट दर 6,000 रुपये प्रति वर्गफुट की दर पर 229-253 वर्गफट की 19 दुकानें लीज होल्ड पर उपलब्ध हैं। शारदा चौक योजना के अंतर्गत प्रथम तल में आफसेट दर 6,500 रुपये प्रति वर्गफुट की दर पर 3 नग हाल उपलब्ध हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक हाल 4,430 वर्गफुट का लीज होल्ड पर उपलब्ध है।

बांडे मार्केट योजना

इस योजना में जो कि रायपुर शहर के मध्य स्थित है। फ्री होल्ड में 9 नग दुकानें / हाल जोकि 336 से 4186 वर्गफुट है । आफसेट दर प्रति वर्गफुट प्रथम तल के लिए 1,0213 रुपये, द्वितीय तल के लिए 8,701 रुपये प्रति वर्गफुट तथा तृतीय तल के लिए 8,265 रुपये प्रति वर्गफुट है।

हनुमान मंदिर योजना

शहर के सबसे व्यस्तम चौक शास्त्री चौक के पास एवं रायपुर तहसील कार्यालय के सामने स्थित इस योजना के अंतर्गत लीज होल्ड पर 18 नग दुकानें / हाल जिनका क्षेत्रफल 1800 से 4449 वर्गफुट है। प्रथम तल में 10,000 रुपये प्रति वर्गफुट, द्वितीय तल में 9,900 रुपये प्रति वर्गफुट तथा तृतीय तल में 9800 रुपये की आफसेट दर प्रति वर्गफुट पर उपलब्ध है। इसके साथ ही बोरियाखुर्द योजना में 78 से 327 वर्गफुट के 32 नग दुकानें लीज होल्ड में आफसेट दर 4,000 रुपये प्रति वर्गफुट पर उपलब्ध है।

प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे बुधवार को निविदा में हो सकते हैं शामिल

रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने बताया कि संपत्ति खरीदने के लिए आफसेट दर का 10 प्रतिशत पंजीयन राशि जमा कर प्रत्येक माह के दूसरे एवं चौथे बुधवार को होने वाली निविदा में भाग लेकर दुकानें / हाल को क्रय किया जा सकता है।

कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने वाले तीन नेता पार्टी से निष्कासित

प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बोले- पार्टी पर नहीं पड़ेगा कोई असर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी दो दिन की समीक्षा बैठकों के बाद अब बागियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सोमवार को पार्टी ने जगदलपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल के खिलाफ प्रचार करने वाले तीन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें पूर्व महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष कमल झज्ज, विक्रम शर्मा और कुक्की झारी शामिल हैं। इन्हें छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। जतिन ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज से शिकायत की थी। आलाकमान के निर्देश पर जगदलपुर में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने यह कार्रवाई की है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दावा किया है कि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। पार्टी तो किसी एक को ही टिकट देगी लेकिन बाकी लोगों को मिलकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ेगा तो कार्रवाई तो होगी ही। इससे पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस जीतकर आ रही है। बैज ने कहा कि पार्टी के पास और भी शिकायतें आई हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

सैलजा ने की थी वन टू वन चर्चा

बीते शनिवार और रविवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने दो दिन तक प्रदेश के सभी कांग्रेस प्रत्याशियों से वन टू वन चर्चा की थी। विधायकों से भी चुनाव की स्थिति की टोह लेती रहीं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सैलजा ने सीधे-सीधे पूछा है कि क्या आप चुनाव जीत रहे हैं? जीत रहे हैं तो जीत का अंतर क्या होगा? अगर हार गए तो किसकी वजह से हारेंगे? किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया? कुछ प्रत्याशियों ने सैलजा को भितरघात करने वालों की नाम के साथ शिकायत की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 30 प्रतिशत सीटों पर बागियों ने पार्टी के विरोध में प्रचार-प्रसार व अन्य गतिविधियां की हैं। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी ने अब तक 25 से अधिक विधानसभा सीटों पर भितरघात करने वाले करीब 50 नेताओं पर निष्कासन, निलंबन व अन्य कार्रवाई की है। वहीं आधा दर्जन से अधिक नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

कांग्रेस की समीक्षा रिपोर्ट ही चुनाव का एग्जिट पोल-केदार गुप्ता

इधर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस की ओर से की जा रही कार्रवाई पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कितनी अंतर्कलह है, यह उसकी समीक्षा बैठकों के बाद सामने आ रहा है। कांग्रेस कई टुकड़ों में बंट चुकी है। उसकी समीक्षा बैठक ही छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जो बता रहा है कि जनता ने उन्हें ठुकरा दिया है। परिणाम आए नहीं, लेकिन सिर फुटव्वल चल रही है।

झीरम पर फैसला न्याय का दरवाजा खोलने जैसा - भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम कांड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर कहा है कि झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। झीरम कांड दुनिया के लोकतंत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड था। इसमें हमने दिग्गज कांग्रेसी नेताओं सहित 32 लोगों को खोया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे के वृहत राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज रास्ता साफहो गया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। किसने किसके साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रचा था, सब साफहो जाएगा। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि झीरम के शहीदों को एक बार फिर श्रद्धांजलि।

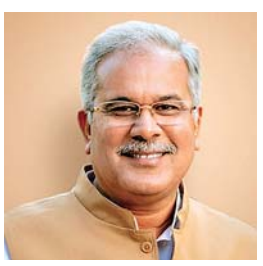

RNI No. CHHHIN/2011/38292

भारत सम्मान NEWS

अम्बिकापुर, बुधवार, 22 नवम्बर 2023

पटरी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे, नाराज हाई कोर्ट ने कहा- यहां कोई सिस्टम है या नहीं

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई है कि जीआरपी और आरपीएफ के रहते स्कूली बच्चे जान को जोखिम में डालकर पटरी पार कर स्कूल जा और वापस आ रहे हैं। नाराज कोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन के अलावा रेलवे के वकील से पूछा कि कोई सिस्टम है या नहीं। कोर्ट ने केंद्र व राज्य शासन के अलावा रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि तय कर दी है।

अखबार में प्रकाशित खबर को स्वत: संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। नाराज कोर्ट ने शासन के विधि अधिकारियों व रेलवे के अधिवक्ता से पूछा कि यह सब क्या है। रेलवे जैसे बेहद संवेदनशील विभाग में कोई व्यवस्था सुचारू रूप से काम करता भी है या नहीं। यह सब क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन के सामने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी आशंका जाहिर की और कहा कि छुट्टी के समय वापसी में भी बच्चे निश्चित तौर पर ऐसे ही पटरी पर कर घर भी जाते होंगे। कोर्ट ने पूछा कि रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है भी या नही। तब कोर्ट को बताया गया कि जीआरपी और आरपीएफ की तैनाती रहती है।

कोर्ट ने पूछा- फोर्स क्या करता है

विधि अधिकारियों ने बताया के राज्य शासन के अलावा रेलवे पुलिस फोर्स की भी तैनाती रहती है। कोर्ट ने पूछा कि भारी-भरकम अमल के बाद बच्चों की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं कि जा रही है। इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

फुट ओवर ब्रिज की मांगी रिपोर्ट

डिवीजन बेंच ने पूछा कि लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए रेलवे ने व्यवस्था की है या नहीं। फुट ओवर ब्रिज के संबंध में कोर्ट ने पूछा व विस्तृत रिपोर्ट पेश करने रेलवे को निर्देश जारी किया है।

रेलवे अफसरों की लापरवाही आई सामने

बिलासपुर रेलवे स्टेशन के दूसरी ओर तकरीबन तीन लाख लोग निवास करते हैं। लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) सालों पहले टूट चुका है। रेलवे ने नया एफओबी बनाने का काम शुरू तो किया था, लेकिन चार साल बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया। यहां के निवासी रेलवे के अफसरों से लंबे समय से एफओबी का काम पूरा करने की मांग कर रहा है। जिस जगह से बच्चे पटरी पार करते हैं वहां पर यदि मालगाड़ी ज्यादा देर खड़ी रहती है तो उसके केबिन में चढ़कर पटरियों को पार करना बच्चों की मजबूरी हो जाती है। इसके अलावा सैकड़ों अन्य लोग भी रोजाना पटरियों को पार करते हैं। इसके बावजूद रेलवे अब तक एफओबी का निर्माण पूरा नहीं करा रहा है।

अधेड़ से मारपीट, जुर्म दर्ज

रायपुर। ग्राम खट्टी मिलन चौक में पांच युवकों ने एक राय होकर अधेड़ से गाली-गलौज कर बेल्ट से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी आस्तोराम साहू 55 ग्राम खट्टी का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी मिलन चौक के तरफ घुमने गया था, तभी आरोपी खुमेश्वर यादव, गुमान ध्रुव व अन्य 3 युवक प्रार्थी के पास आए और प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किए। प्रार्थी की शिकायत पर अभनपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 294, 506, 323 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

सिटी सेंटर माल के पास खड़ी बाइक पार

रायपुर। सिटी सेंटर माल के सामने खड़ी बाइक को अज्ञात चोर ने पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मनोज कुमार सिंद्रामे 34 वर्ष शिवानंद नगर सेक्टर 1 का रहने वाला है। बताया जाता है कि प्रार्थी अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 सीटी 9706 को सिटी सेंटर माल के सामने खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 10 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

हारवेस्टर वाहन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत

रायपुर। ग्राम सरारीडीह में हारवेस्टर वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक टिकेश्वर वर्मा 53 वर्ष ग्राम सरारीडीह का रहने वाला है। बताया जाता है कि मृतक अपने खेत में हारवेस्टर से धान कटाई करवा रहा था। तभी चालक ने अपने हारवेस्टर वाहन क्रमांक पीबी 13 बीआर 2479 को लापरवाही पूर्वक चलाकर टिकेश्वर को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में टिकेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में नेवरा पुलिस ने हारवेस्टर को जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की है।

थाने के सामने परिवार सहित केबल संचालक का अपहरण, लूटपाट के बाद छोड़ा

बिलासपुर । सरकंडा थाना के सामने कार की टक्कर होने पर कुछ युवकों ने केबल व्यवसायी की पिटाई उसके परिवार के सामने कर दी। इसके बाद केबल व्यवसायी और उसके परिवार को जबरन मोपका चौक तक लेकर गए। वहां पर जान से मारने की धमकी देकर 15 हजार रुपए लूट लिए। साथ ही कार की रिपेयरिंग के नाम से 25 हजार रुपए फोन-पे करा लिए। घटना से डरकर केबल व्यवसायी अपने घर लौट गए। बाद में उसने घटना की शिकायत सरकंडा थाने में की है। इस पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज कर जांच में लिया है।

बलौदा बाजार जिले के भाठापारा में रहने वाले आसिफ अली केबल संचालक हैं। रविवार को वे अपनी पत्नी शाहिना खान, पड़ोसी लक्ष्मी डहरिया और बच्चों को लेकर लुतरा जा रहे थे। अपनी कार से वे सरकंडा थाना के सामने बहतराई चौक के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सामने चल रहे कार के चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया। इससे पीछे चल रहे आसिफ की कार सामने की कार से टकरा गई। टक्कर के बाद सामने चल रहे कार में सवार युवक उतरकर आसिफ के पास आए। उन्होंने आसिफ को खींचकर बाहर निकाला। इसके बाद उनकी पिटाई कर दी। मारपीट के बाद एक युवक उनकी कार में बैठ गया। युवक केबल संचालक को मोपका चौक लेकर गया। वहां पर जान से मारने की धमकी देकर केबल व्यवसायी से 15 हजार लूट लिए। साथ की कार की रिपेयरिंग के नाम पर 25 हजार रुपए फोन-पे पर ट्रांसफर करा लिया। घटना से डरे केबल व्यवसायी भाठापारा परिवार सहित लौट गए। इसके दूसरे दिन बिलासपुर आकर उन्होंने सरकंडा थाने में शिकायत की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

पुलिस को नहीं लगी भनक

मारपीट और अपहरण की यह पूरी घटना सरकंडा थाने महज चंद कदम की दूरी पर हुई। इधर इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं लग सकी। लूट और मारपीट के बाद डरा हुआ केबल संचालक अपने घर लौट गया। स्वजन को पूरे मामले की जानकारी देने के बाद दूसरे दिन वे थाने पहुंचे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया है। वहीं, अब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।

कुसमुंडा में युवक की हत्या के बाद दहशत का माहौल

कोरबा-रायपुर। दर्री थानांतर्गत साडा कॉलोनी में एक व्यक्ति की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मग कायम कर मामला जांच में लिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि मृतक टाटा मोटर्स छूरी में कार्यरत नरेंद्र पाल सिंह उर्फरोजी है। वहीं आरोप सुमित दास नामक ने उसकी हत्या की है। जानकारी के अनुसार, कोरबा के दर्री थाना क्षेत्र में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। साडा कॉलोनी निवासी सुमित दास नामक व्यक्ति ने कुसमुंडा निवासी नरेंद्र पाल सिंह उर्फरोजी की प्राण घातक हमला कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, मृतक रोजी छुरी के टाटा मोटर्स में कार्यरत है, जो बीती रात आरोपी के घर किसी काम से गया हुआ था। यही किसी बात को लेकर मृतक का आरोपी से विवाद हुआ। जिसके बाद आरोपी ने रोजी की हत्या कर दी। आरोपी सुमित दास मुंबई की एक कंपनी में ऑनलाईन काम करता है और साडा कॉलोनी स्थित ऋषभ कश्यप के घर पर किराए के मकान में रहता है।

धान काटने के हार्वेस्टर में दबकर युवक की मौत

महासमुंद। जिले के बसना थाना क्षेत्र के बड़े ढाबा गांव मे धान काटने का हार्वेस्टर पलट गया. इस हादसे में एक 20 वर्षीय युवक की दबने से मौत हो गई है. मृतक के खेत में धान कटाई का काम चल रहा था. इसी दौरन हार्वेस्टर में कुछ खराबी आ गई जिसे ठीक कराने के लिए युवक उसे मेकेनिक के पास लेकर जा रहा था. तभी रास्ते में अचानक हार्वेस्टर पलट गया जिसकी चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गयी. बसना पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम ताराचंद बारीक है, जो कि बड़े ढाबा गांव का ही रहने वाला था. घटना के बाद आसपास काम कर रहे लोगों की भीड़ लग गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने झीरम हत्याकांड के बलिदानियों को न्याय दिलाने का रास्ता खोला: अभयनारायण

बिलासपुर। झीरम हत्याकांड को लेकर एनआइए द्वारा दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस इस घटना की जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला एनआइए ने दायर किया था। पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र की जांच शुरू की और एनआइए ने अदालती अड़ंगा अटका दिया। पहले वे ट्रायल कोर्ट गए वहां उनकी याचिका खारिज हुई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभयनारायण राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की स्वागत करती है। कांग्रेस का मानना है कि इस फैसले से बलिदानी परिवारों को न्याय मिलने का रास्ता खुला है। अब पुलिस 26 मई 2020 को दर्ज दूसरी एफआइआर के आधार पर यह जांच कर पाएगी कि किसके कहने पर और किसे बचाने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसी एनआइए जांच का रास्ता रोक रही थी। कांग्रेस ने कहा कि हमारा सवाल है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने आपराधिक षड़यंत्र की जांच क्यों नहीं करवाई।

षड़यंत्रकारियों का होगा पर्दाफाश, पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय- रश्मि सिंह

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह ने स्वागत करते हुए कहा कि इस फैसले से झीरम हत्याकांड के पीड़ित परिवारजनों को राहत मिलेगी। षड़यंत्रकारी सामने आएंगे और यह पता चलेगा कि इस हत्याकांड में आखिर संलिप्तता किसकी रही है। क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस को अब जांच का अधिकार मिल गया है। केंद्र सरकार अभी तक अड़ंगा लगाते आ रही थी। आरोपितों को अब तक बचाते आ रही थी। यह भी एक बड़ा सवाल है कि केंद्र सरकार क्यों अड़ंगा लगा रही थी। यह भी एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस झीरम कांड का जांच करेगी। अब षड़यंत्रकारियों के ऊपर से पर्दा उठेगा। षड़यंत्रकारियों का असली चेहरा सामने आएगा और बेनकाब भी होंगे। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सब स्वागत करते हैं।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक जितेन्द्र जायसवाल द्वारा जायसवाल प्रिंटिंग प्रेस राघवपुरी, डीगमा, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एवं मुद्रित। संपादक जितेन्द्र जायसवाल। मो.नं.-09424262547